हल्द्वानी (नैनीताल) एवं देहरादून से एक साथ प्रकाशित

समाचारों को विस्तार से व तत्काल पढ़ने के लिए क्लिक करें
Web:- www.jokhimnews.com
सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में "A" श्रेणी में सूचीबद्ध

जोखिम

भय भूख एवम् भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत् निर्भीक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

वर्ष : 16 अंक : 106 हल्द्वानी (नैनीताल) गुरूवार 26 फरवरी 2026 मूल्य रू 2 पृष्ठ : 8

शिक्षा निदेशालय विवाद पर रामनगर में कांग्रेस का प्रदर्शन

रामनगर (संवाददाता)। देहरादून में शिक्षा निदेशालय में हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में एकत्र हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए उमेश शर्मा और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देहरादून में शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौड़ियाल के साथ हुई मारपीट की घटना बेहद गंभीर है और इससे प्रशासनिक व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंची है। पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि किसी अधिकारी के साथ उसके ही दफ्तर में मारपीट होना बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है।कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष रामनगर देशबंधु रावत, ब्लॉक अध्यक्ष मालधन ओम प्रकाश, महिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष ललिता उपाध्याय, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल खुलासा, एडवोकेट दीप्ति भारद्वाज, हर्ष रावत, नजाकत अली, अनीश खान, वीरेंद्र लटवाल, गोपाल रावत, कुबेर बिष्ट, चाँद खान, वीरेंद्र तिवारी, उमाकांत ध्यानी, ओम प्रकाश आर्यवंशी, अफाक हुसैन, कन्नू जोशी आदि मौजूद रहे।

कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

अल्मोड़ा (संवाददाता)। जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कहा कि उत्तराखंड में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध, चोरी, लूट, नशे का कारोबार तथा हत्या जैसी वारदातें आम होती जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में आम नागरिक

ही नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों पर भी मारपीट जैसे आरोप सामने आ रहे हैं और अल्मोड़ा जैसे शांत शहर में भी अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं के बावजूद पुलिस अभी तक एक आरोपी बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है और राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, पुलिस तंत्र को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए और महिलाओं सहित आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस जनहित में आंदोलन करने को बाध्य होगी।

प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार आन्दोलन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् में तृतीय दिवस को भी जारी रहा

रामनगर (संवाददाता)। शिक्षा निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा देहरादून में निदेशक से मारपीट एवं अभद्रता प्रकरण में चल रहे प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार आन्दोलन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् में तृतीय दिवस बुधवार को भी जारी रहा। यह धरना प्रदर्शन विभिन्न संगठनों के प्रान्तीय स्तर पर गठित अधिकारी-शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में किया जा रहा है। तीसरे दिन धरना स्थल पर वक्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ उक्त घटना पर आक्रोश व्यक्त किया और तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर सरकारी संस्थानों में अधिकारियों-शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भय के माहौल को दूर करने के लिए इस विषय पर एसओपी जारी करने की मांग की गई, साथ ही यह भी मॉग की गई कि कुछ कर्मचारियों पर बेवजह गलत तरीके से दर्ज की गयी एफआईआर तुरन्त वापस ली जाए।धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी,मण्डलीय उपाध्यक्ष एजूकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसोशिएशन उत्तराखण्ड नवीन चंद्र घिल्डियाल, गरिजा भूषण गुरूरानी,विजय मासीवाल,मनमोहन सिंह,भूपेन्द्र सिंह, अमित भट्ट, दिलीप मेहता आदि ने सम्बोधित किया।

उच्च शिक्षा भ्रमण प्रशिक्षण से लौटे डॉ. दीपक खाती एवं डॉ. ममता जोशी का हुआ महाविद्यालय में स्वागत

रामनगर (संवाददाता)। उत्तराखंड सरकार की उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों से आए 40 प्राध्यापकों का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन भ्रमण 16 फरवरी से 21 फरवरी तक इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रयागराज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने प्रयागराज के गौरवशाली स्थलों त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद किला, आनंद भवन, खुसरो बाग, सरस्वती घाट, हनुमान मंदिर और इलाहाबाद संग्रहालय का अवलोकन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कॉमर्स संकाय, अर्थशास्त्र विभाग और विज्ञान संकाय - इन स्थलों ने भारतीय इतिहास, आध्यात्मिकता और राष्ट्रनिर्माण की प्रेरणा से सभी को ओत-प्रोत कर दिया।राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर के वाणिज्य विभाग के डॉ. दीपक खाती एवं डॉ. ममता भदोला जोशी के शैक्षिक यात्रा सम्पन्न कर महाविद्यालय पहुंचने पर प्राचार्य प्रो. एम सी पाण्डे, चीफप्रॉक्टर प्रो. एस एस मौर्य सहित महाविद्यालय परिवार ने दोनों का स्वागत किया। उन्होंने अपने अनुभव में कहा कि ऐसे शैक्षिक भ्रमण केवल यात्रा नहीं होते, बल्कि विविध ज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत संगम होते हैं, जो हमें नई ऊर्जा, व्यापक दृष्टि और नवाचार की प्रेरणा प्रदान करते हैं । यही प्रेरणा भविष्य की पीढ़ियों के उज्ज्वल निर्माण का आधार बनेगी।शैक्षिक यात्रा के क्रम में सभी प्राध्यापकों ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया तथा सारनाथ में भगवान बुद्ध के ज्ञान संदेश से प्रेरणा प्राप्त की।

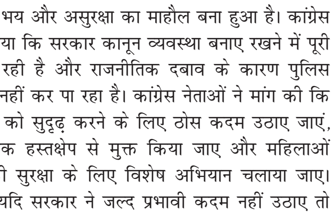

सम्पादकीय

सौदा पारदर्शी हो

बड़ी ताकतें अपनी कंपनियों को सौदा दिलवाने के लिए भारत को महज एक बाजार के रूप में देखती हैं। मगर भारत को उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। यह भी जरूरी है कि सौदा पारदर्शी हो, ताकि उसको लेकर विवाद पैदा ना हो।फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने का फैसला तत्कालीन यूपीए सरकार ने किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने उसे आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने खरीदारी की शर्तों में उलटफेर कर दी। इसी कारण मोदी सरकार ने जब पहली बार राफेल विमानों को खरीदा, तो उस सौदे पर ना सिर्फ भारत, बल्कि फ्रांस में भी बड़े विवाद हुए। दोनों जगहों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मगर वह दीगर मामला है। उस विवाद को विमानों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं माना जाएगा। हां, पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई भारतीय राफेल विमानों को मार गिराने का दावा किया था, तो जरूर विमानों की तत्परता से संबंधित प्रश्न उठे।बहरहाल, उस दावे की सच्चाई क्या है, इस बारे में भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। इस बीच चार दिन के उस सीमित युद्ध ने भारत की रक्षा तैयारियों में और दम लगाने की जरूरत निर्विवाद रूप से जाहिर किया। यह भी साफ हुआ कि आगे की लड़ाइयों में वायु सेना की प्रमुख भूमिका होगी। अतः भारतीय वायु सेना की लड़ाकू विमानों की जरूरत को पूरा करना अनिवार्य है। अब केंद्र ने 114 राफेल विमानों को खरीदने का जो फैसला किया है, उसे इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फ्रेंच कंपनी दसॉ के राफेल विमान उन्नत तकनीक से लैस हैं, यह आम धारणा है। चूंकि भारत के पास पहले ये विमान हैं, इसलिए उन्हें ही खरीदना भी सही निर्णय माना जाएगा। अब समझ यह बनी है कि आधुनिक हथियार एवं उपकरण उच्च तकनीक से संचालित हैं, वैसे में एक जैसे सिस्टम अधिक कारगर हो रहे हैं। इसलिए भारत को अलग-अलग देशों से सिस्टम खरीदने की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। बड़ी ताकतें अपनी कंपनियों को सौदा दिलवाने के लिए भारत जैसे देशों को महज एक बाजार के रूप में देखती हैं। मगर भारत को उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। उसे अपनी जरूरतों के अनुरूप सौदे करने चाहिए। फिर यह भी जरूरी है कि हर सौदा पारदर्शी हो, ताकि उसको लेकर उस तरह का संदेह पैदा ना हो, जैसा पिछले राफेल सौदे के समय हुआ था।

भाजपा को लेने के देन पड़ेगे

क्या भाजपा राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कराने और जीवन भर चुनाव लड़ने से रोकेगी? ऐसे ही क्या प्रियंका गाधी वाड्रा की भी सदस्यता खत्म कराने की पहल होगी? भाजपा की ओर से पहले राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की चर्चा थी लेकिन उसको पता है कि उसमें पार्टी को शामिल होना होगा। यह भी सवाल था कि अगर सरकार के नीतिगत फैसलों की आलोचना के लिए विपक्ष के किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाने लगे तो फिर यह बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तभी पार्टी के एक सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सबस्टेंसिव मोशन पेश कराया गया।ध्यान रहे पहले सबस्टेंसिव मोशन पर यूपीए की पहली सरकार ने कई सांसदों की सदस्यता समाप्त की थी। उनके ऊपर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगे थे। बाद में कमीशन लेकर एमपी फंड बेचने के आरोप में भी इस तरह का प्रस्ताव लाया गया। लेकिन राहुल गांधी का मामला अलग है। राहुल एक तो नेता विपक्ष हैं और दूसरे देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई बहुत मजबूत आधार नहीं है। फोर्ड फाउंडेशन से संबंध या जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध रखना सदस्यता खत्म करने का आधार नहीं हो सकता। तभी ऐसा लग रहा है कि भाजपा सांसद की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव का इस्तेमाल राहुल को डराने और दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर है। राइट विंग इकोसिस्टम के लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर राहुल की सदस्यता चली जाती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगी। अगर ऐसा होगा तो पार्टी के अंदर पावर सेंटर बदल जाएगा। यानी इस तरह से राहुल से पीछा छूटने की भाजपा के नेता उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है।वैसे भाजपा नेताओं का एक समूह प्रियंका के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

बच्चों को सोशल मीडिया के असर से बचाने की जरुरत

अजीत द्विवेदी

देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सम्मेलन चल रहा है। एआई के आर्थिक, सामरिक इस्तेमाल और उसके असर की व्याख्या हो रही है। दुनिया भर के विशेषज्ञ दिल्ली में हैं। और इसके समानांतर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कैसे बचाया जाए। जब से ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है और सभी सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी बच्चे का अकाउंट उनके प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए तब से भारत और दुनिया भर के देशों में इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है। भारत में आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से इसकी पहल हो रही है कि 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे दूर रखा जाए। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के टेम्पलेट का इस्तेमाल करके यहां भी पाबंदी लगाई जाए।इसके साथ ही इस प्रतिबंध के असर को लेकर भी बहस छिड़ गई है। यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी बच्चों को इसके असर से बचाने का रामबाण उपाय है? इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाबंदी का समर्थन और विरोध करने वाले दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया के असर से बचाने की जरुरत है। बचाने के तरीके को लेकर जरूर मतभेद हैं। अमेरिका और यूरोप में कुछ दिन पहले हुए सर्वेक्षणों से पता चला कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जेन जेड यानी 1997 से 2013 के बीच जन्मे बच्चे अपने से पहले वाली पीढ़ी यानी मिलेनियल्स के मुकाबले कम बुद्धिमान हैं। यह पहली बार है, जब कोई पीढ़ी अपने से पिछली पीढ़ी से कम बुद्धिमान हैं और इसका मुख्य कारण स्मार्ट फोन या दूसरे स्मार्ट गैजेट्स और सोशल मीडिया है। टेलीविजन को भी इडियट बॉक्स कहते थे लेकिन उसने बच्चों के सोचने, समझने की क्षमता को उतना प्रभावित नहीं किया, जितना इंटरनेट से कनेक्टेड गैजेट्स और सोशल मीडिया ने किया है।सोचें, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि की वजह से दुनिया संज्ञानात्मक क्रांति (कॉग्निटिव रिवोल्यूशन) के मध्य में है और दूसरी ओर संचार क्रांति ने एक पूरी पीढ़ी की बुद्धिमता छीन ली है! क्या कृत्रिम बुद्धिमता के फलने फूलने के लिए जरूरी है कि प्राकृतिक बुद्धिमता का क्षरण हो? बहरहाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ बच्चों और किशोरों की संज्ञानात्मक क्षमता को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी सामाजिकता और मानसिक व शारीरिक क्षमता को भी प्रभावित कर रहे हैं। बच्चे और किशोर निराशा और अवसाद का शिकार हो रहे हैं। उनके अंदर कुंठा बढ़ रही है और सामाजिकता कम होती जा रही है। वे अपनी एक दुनिया रचने लगे हैं और कई बार यह उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले ही दिनों दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तीन बहनों के आत्महत्या करने की खबर आई थी। उनको सोशल मीडिया की ऐसी लत लगी थी कि वे अपनी वास्तविक दुनिया से बेखबर हो गईं थीं और एक आभासी दुनिया में रहने लगी थीं, जिसकी परिणति तीनों की मृत्यु में हुई।लेकिन क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने और बच्चों व किशोरों को स्क्रीन एडिक्शन यानी फोन व सोशल मीडिया की लत से बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाए? ध्यान रहे कोई भी पाबंदी बहुत खराब आर्थिक नीति मानी जाती है लेकिन यह सिर्फ आर्थिक नीति का मामला नहीं है, बल्कि इसके दूसरे पक्ष भी हैं। उन सबको ध्यान में रख कर ही कोई भी प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें भेड़चाल के लिए कोई जगह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी लगा दी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी टिकटॉक से लेकर, यूट्यूब, स्नैपचौट, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए पाबंदी लगाने की योजना का ऐलान किया है। इसकी देखादेखी कुछ और देश ऐसा करेंगे और भारत में भी इसकी मांग होगी और लोकप्रिय भावना को संतुष्ट करने के लिए हो सकता है कि कुछ कदम उठा भी लिए जाएं लेकिन उससे कोई समाधान नहीं होगा।सबसे पहले तो यह समझने की जरुरत है कि बच्चों और किशोरों में स्क्रीन की जो लत लगी है वह टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की समस्या नहीं है। यह एक सामाजिक व पारिवारिक समस्या है, जिसमें तकनीक को विलेन बनाया जा रहा है। इसके समाधान के लिए सबसे पहले यह सवाल पूछने की जरुरत है कि स्क्रीन का एडिक्शन पहले किसको हुआ? सोशल मीडिया की लत पहले किसको लगी? क्या ऐसा नहीं कि परिवार के बड़े, बुजुर्ग पहले इस लत का शिकार हुए और फिर बच्चों की बारी आई? क्या यह सही नहीं है कि कोरोना महामारी के बाद की स्थितियों ने भी इस परिघटना को जन्म दिया? क्या पढ़ाई, लिखाई में स्मार्ट फोन या स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? जाहिर है यह एक संश्लिष्ट समस्या है, जिसका समाधान पाबंदी के एक कामचलाऊ तरीके से निकालने की कोशिश हो रही है। अगर इसकी बहुआयामी जटिलता को समझते हुए समाधान निकालने का प्रयास नहीं हुआ तो पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा।वैसे भी किसी भी चीज पर पाबंदी कभी भी कामयाब नहीं होती है, बल्कि उससे समस्या उलझती जाती है और साथ ही नई समस्याएं भी पैदा होती हैं। वैसे भी बच्चों या किशोरों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोकना एक मुश्किल काम होगा। भारत जैसे देश में यह और भी मुश्किल होगा। पहले तो सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने वाले के उम्र और पहचान का वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल होगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी दस्तावेज जमा कराए जाते हैं तो प्राइवेसी कंप्रोमाइज्ड होने से लेकर पहचान के दुरुपयोग का खतरा अलग पैदा होगा।इस तरह की पाबंदियों से बच्चों और किशोरों को, जो तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम और जानकार हैं, डार्क वेब या दूसरे गोपनीय तरीके आजमाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसके एक नया खतरा पैदा हो सकता है। इसी तरह कई बार सोशल मीडिया बच्चों व किशोरों को तनाव से निकलने का रास्ता भी देता है। वे अपने हमउम्र बच्चों से इससे जुड़े होते हैं, जिनसे उनको भावनात्मक संबल मिलता है। कई जानकार यह भी मानते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में इस तकनीक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक भूमिका रही है। इन पर पाबंदी महिलाओं को, खास कर युवा महिलाओं को निगेटिव तरीके से प्रभावित करेगी। ध्यान रहे भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का इंटरनेट एक्सेस बहुत कम है।तभी सवाल है कि अगर पाबंदी कोई समाधान नहीं है तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को न्यूनतम जांच सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया जाए। इसके बाद उनके कंटेंट को लेकर भी उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सुनिश्चित करना होगा कि किस किस्म का कंटेंट कौन एक्सेस करेगा। इसके बाद अश्लील और हिंसक कंटेंट को पूरी तरह से रोकने का नियम बनाने की जरुरत है। भारत में गेमिंग को रेगुलेट करने के नियम आए हैं। एडिक्ट करने वाले गेम और अश्लील कंटेंट को रोकने के सख्त नियम बनाए जाएं और उनको लागू कराया जाए।पैरेंटल कंट्रोल को आसान बनाया जाए ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी अपने घर के स्मार्ट गैजेट्स में इसका इस्तेमाल करके यह तय कर सकें कि उनके बच्चे क्या कंटेंट देख सकते हैं।

हिन्दी दैनिक जोखिम

शिक्षा निदेशक पर हमले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

ऋषिकेश(संवाददाता)। बेसिक शिक्षा निदेशक पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि सरकारी कार्यालय में घुसकर शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ अभद्रता और मारपीट लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। यदि जनप्रतिनिधि ही कानून को हाथ में लेंगे तो कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े होंगे। कांग्रेस ऐसे कृत्यों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। डोईवाला कांग्रेस नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि भाजपा के विधायक और उनके समर्थकों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला किया जाना निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल तोड़ती हैं। न्याय न मिलने की स्थिति में कांग्रेस को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र स्वरूप भट्ट ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति जताने के संवैधानिक तरीके मौजूद हैं। हिंसा और दबाव की राजनीति किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। सरकार को तुरंत दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन में मनोज नौटियाल, गौरव मल्होत्रा, राहुल सैनी, स्वतंत्र बिष्ट, अमित सैनी, आरिफ अली, मोहित कपरवान, आशिक अली, रेखा कांडपाल सती, रीता क्षेत्री, साहिल अली, संजीव भट्ट, राहुल आर्य, हर्षित उनियाल, विमल गोला, मनोज पाल, महिपाल रावत आदि उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार...

झड़ीपानी में उत्तर रेलवे की भूमि पर कब्जे को लेकर नोटिस, लोगों ने किया विरोध

देहरादून(संवाददाता)। झड़ी पानी स्थित उत्तर रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म है। इस बार रेलवे ने आशु गुप्ता पुत्र पदम गुप्ता को नोटिस देकर अनाधिकृत कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। इसका स्थानील स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। कहा कि रेलवे बार बार स्थानीय लोगों को धमका कर उनकी रजिस्ट्री की भूमि को अपना बता परेशान कर रहा है। उत्तर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर शिव सिंह रावत के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। लोगों के कड़े विरोध को देखते हुए कार्रवाई नहीं कर पाई व समझौता हुआ। निर्णय लिया गया कि संयुक्त रूप से भूमि सीमांकन नपत के लिए नगर पालिका, राजस्व विभाग व रेलवे की संयुक्त टीम गठित किया जाना उचित होगा। टीम द्वारा विधिवत, संबंधित पक्षकारों के सम्मुख सीमांकन की कार्रवाई की जाएगी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीमांकन की कार्रवाई तक कोई पक्ष मौके पर निर्माण कार्य नहीं करेंगे, तथा भूमिधरी की व रेलवे की सीमा का निर्धारण किया जाना है। इस पत्र में दोनो पक्षों के हस्ताक्षर किए। कानूनगो विनोद जोशी ने कहा कि रेलवे व स्थानीय व्यक्ति के बीच सीमा विवाद के कारण यहां आए हैं। इसमें दोनों पक्ष के बीच तय हुआ है कि नगर पालिका व रेलवे के द्वारा संयुक्त सीमांकन किया जाएगा। पहले सीमांकन किया जा चुका है लेकिन अब पुनः सीमांकन किया जाएगा। भूमिधरों के प्रतिनिधि अजय गोयल ने कहा कि रेलवे व भूमिधरों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है व पहले भी दो बार नगर पालिका व राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन कर मुनारबंदी की जा चुकी है लेकिन रेलवे सहयोग नहीं कर रहा है।

थंडर ब्वॉयज और रायपुर इलेवन सेमीफाइनल में

देहरादून(संवाददाता)। 56 वें अमर शहीद खड़क बहादुर बिष्ट मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में थंडर ब्वॉयज ने राजपुर एफसी को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। दूसरे मैच में रायपुर इलेवन ने सडनडेथ में 12 गढ़वाल राइफल्स को 5-4 से हराया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बुधवार को थंडर ब्वॉयज व राजपुर एफसी के बीच खेला गया पहला क्वार्टर फाइनल मैच संघर्षपूर्ण रहा। खेल के 31 वें मिनट में थंडर ब्वॉयज के फॉरवर्ड आशीष ने गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। अभी राजपुर एफसी के खिलाड़ी संभल भी नहीं पाए थे कि एक मिनट बाद सचिन ने गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। 33 वें मिनट में राजपुर एफसी के फॉरवर्ड प्रियांशु ने गोल दाग स्कोर 2-1 कर दिया। 41 वें मिनट में राजपुर एफसी के आर्यन ने टीम लिए दूसरा गोल मैच को रोमांचक बना दिया। हालांकि, 58वें मिनट में थंडर ब्वॉयज के सचिन ने गोल दागकर टीम की 3-2 से जीत सुनिश्चित कर दी। 32वें मिनट में राजपुर आयुष को रेड कार्ड मिलने के बाद टीम को 10 खिलाड़ी से खेलना पड़ा। सचिन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 12 गढ़वाल राइफल्स व रायपुर इलेवन के खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। सडनडेथ तक खिंचे मुकाबले में रायपुर इलेवन ने 5-4 से बाजी मारी। रायपुर इलेवन के लिए शाश्वत, शिवम पंत, नाट्टी, कुणाल और करण ने गोल किए। जबकि 12 गढ़वाल राइफल्स की ओर से परवेश, सुचारू, प्रवेश रावत व अभिषेक ही गोल करने में सफल रहे। रायपुर के शिवम पंत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। शुक्रवार को टूर्नामेंट में जीयू एफसी व हिमालयन एफसी और प्रेरणा एफसी व बालाजी ब्वॉयज के क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे।

रोडवेज चालक ने कार्यालय में काटा हंगामा

ऋषिकेश(संवाददाता)। रोडवेज डिपो कार्यालय में एक संविदा बस चालक ने जमकर हंगामा काटा। कर्मचारियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जिसके चलते डिपो प्रशासन ने उसकी सेवा समाप्ति कार्यवाही की संस्तुति कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। बुधवार सुबह यात्रा बस अड्डे स्थित रोडवेज कार्यालय में अचानक एक संविदा चालक हुडदंग करते हुए आ धमका। उसके कई तरह के इशारों के साथ ही अजीबों-गरीब व्यवहार से कर्मचारी भी सकते में आ गए। किसी ने मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने की बात कही, तो कोई किसी ने कुछ ओर कहा। कार्यालय में घंटेभर तक चले चालक के हंगामे के बीच कर्मचारियों ने उसे समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह बाज नहीं आया, जिसके चलते उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए एजीएम अंजलिका शर्मा ने सेवा समाप्ति की संस्तुति कर मुख्यालय को भेज दी। वहीं, कुछ कर्मचारियों ने बताया कि यह कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले ही चालक इसी तरह की हरकतें कर चुका है। एजीएम ने बताया कि चालक धर्मेंद्र ने इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करने को लेकर कार्यालय को एक शपथ-पत्र भी दिया था। बावजूद, वह बाज नहीं आया है। लिहाजा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बताया कि कर्मचारियों के साथ ही चालक-परिचालकों को अनुशासित रहने के लिए पहले से ही कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

महंत पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी हो

ऋषिकेश(संवाददाता)। श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर की भूमि पर कथित अतिक्रमण और मंदिर के महंत रामेश्वर गिरी पर हमले को लेकर संत समिति ऋषिकेश ने विरोध जताया है। समिति ने बुधवार मंदिर परिसर में बैठक कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। समिति के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि ऋषिकेश क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा धार्मिक संपत्तियों का स्वरूप परिवर्तन कर उनका व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की धार्मिक पहचान को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्टों ने पूर्व संत-महापुरुषों द्वारा स्थापित संपत्तियों का स्वरूप बदलने अथवा उन्हें निजी स्वार्थ में बेचने का प्रयास किया, तो संत समाज इसके खिलाफ व्यापक जन आंदोलन छेड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर सरकार, मुख्यमंत्री और न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। महासचिव महंत रामेश्वर गिरी महाराज ने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों के दौरान मंदिर परिसर में साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा था, तभी कुछ लोगों द्वारा कार्य में बाधा डालते हुए मार्ग अवरुद्ध किया गया और साधु-संतों के साथ मारपीट की गई। इसी घटना के विरोध में यह बैठक बुलाई गई। बैठक में संत समाज ने प्रशासन से मंदिर भूमि की विधिवत जांच, अतिक्रमण की निष्पक्ष पड़ताल और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

विधि विवि की स्थापना होने तक चलेगा आंदोलन

ऋषिकेश(संवाददाता)। रानीपोखरी में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर चल रहा धरना बुधवार को नौवें दिन भी शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रानीपोखरी के लिस्ट्राबाद में चल रहे धरने को संबोधित करते हुए रानीपोखरी न्याय पंचायत के प्रधान सुधीर रतूड़ी ने कहा कि राष्ट्रीय विधि विवि की स्थापना से क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर विकास को गति मिलेगी। उन्होंने सरकार से इस विषय में शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। कहा कि जब तक विवि की स्थापना को लेकर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। धरने में अरुण शर्मा, संदीप भट्ट, अनूप चौहान, अनिल कुमार, नवीन चौधरी, सुधीर रतूड़ी, विक्रम भंडारी, अनीता पंवार, सुमित्रा देवी, मुन्नी देवी आदि उपस्थित रहे।

विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा डोईवाला: गौरव चौधरी

ऋषिकेश(संवाददाता)। डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी ने बुधवार को राज्य वित्त आयोग की संस्तुति और अनुदान से नवनिर्मित मुख्य द्वार का लोकार्पण पूजा-अर्चना और रिबन काटकर किया। उन्होंने कहा कि गांवों का विकास केवल सड़क, नाली और भवन निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गांव की पहचान और सौंदर्यीकरण भी विकास का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विकास के संकल्प के साथ डोईवाला ब्लॉक आगे बढ़ रहा है। ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी ने कहा कि राज्य वित्त आयोग के माध्यम से बने इस द्वार से सिमलास ग्रांट को एक अलग पहचान मिलेगी और यह गांव की सांस्कृतिक छवि को मजबूत करेगा। डोईवाला ब्लॉक के सभी गांवों में योजनाओं का लाभ समान रूप से पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। कहा कि आने वाले समय में अन्य विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी। स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए पंचायत के साथ मिलकर निरंतर प्रयास किए जाएंगे। सिमलास ग्रांट प्रधान सुषमा बोरा ने राज्य वित्त आयोग और ब्लॉक प्रमुख का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नए द्वार के निर्माण से गांव को नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि पंचायत जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आगे भी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारेगी। मौके पर खंड विकास अधिकारी परशुराम सकलानी, ग्राम विकास अधिकारी मनजीत सिंह, पूर्व प्रधान उमेद बोरा, रफल सिंह, अर्जुन, राजन विपिन, रोमित आदि उपस्थित रहे।

भराड़ीसैंण में बजट सत्र : सुरक्षा में चूक नहीं होगी बर्दाश्त

चमोली(संवाददाता)। आगामी नौ मार्च से होने वाले बजट सत्र की तैयारियों के लिए चमोली जिला प्रशासन बुधवार को भराड़ीसैंण पहुंचा। यहां अधिकारियों ने सत्र की तैयारियां परखीं और नौ मार्च से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीएम और एसपी ने कहा कि सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने संबंधित अधिकारियों को भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के दौरान बैरिकेडिंग, वाहन पार्किंग, शौचालय, सफाई, मेडिकल सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, पुलिस आवासीय भवनों की व्यवस्थाओं को समय रहते हुए दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में नेटवर्क/वायरलेस कनेक्टिविटी दुरुस्त करने को कहा। जिलाधिकारी ने शैडो एरिया चिह्नित कर अतिरिक्त संचार साधनों की व्यवस्था करने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी मामले में दिक्कत होने पर अपर जिलाधिकारी एवं विधानसभा सत्र के नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सकते हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने कहा कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो। सत्र के दौरान अन्य प्रदर्शनों की आशंका के कारण विशेष एहतियात बरतने के भी सख्त निर्देश दिए। सुरक्षा-व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, फेरी लगाने वाले, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों और होमस्टे में आने वाले लोगों का सत्यापन गहनता से करने को कहा। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. अभिषेक गुप्ता, कर्णप्रयाग के एसडीएम सोहन सिंह रांगड़, जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी असीम देव आदि मौजूद रहे।

कर्णप्रयाग से दिवालीखाल, नैनीताल हाईवे बना बदहाल

कर्णप्रयाग। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को जोड़ने वाला हाईवे कर्णप्रयाग से दिवालीखाल तक कई जगह बदहाल बना है। अब नौ मार्च से विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी के विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में होना है। ऐसे में इस सड़क को तीन दिनों में ठीक करने के निर्देश जिला प्रशासन ने एनएच को दिए हैं। बुधवार को बजट सत्र की तैयारियों के लिए भराड़ीसैंण जाते वक्त डीएम गौरव कुमार और एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने नैनीताल हाईवे का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सुभाषनगर और जखेड़ में हाईवे की बेहद खराब स्थिति को देखकर डीएम ने नाराजगी जताई। यहां सड़क लंबे समय से बदहाल बनी है। सड़क पर पानी बहने से पैच वर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं जखेड़ में भूधंसाव और भूस्खलन जोन परेशानी बने हैं। सिमली सहित कई जगह हाईवे बदहाल है। डीएम गौरव कुमार ने एनएच रूद्रप्रयाग को सुभाषनगर और जखेड़ में पानी की निकासी करने और दिवालीखाल तक पूरा हाईवे ठीक करने के निर्देश दिए। इस दौरान एनएच के अधिशासी अभियंता ओंकार पांडे भी मौजूद रहे।

सीएचसी में डॉक्टरों की कमी से क्षेत्र के लोग परेशान

नई टिहरी(संवाददाता)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते क्षेत्र के लोगों को उपचार के मसूरी और देहरादून की दौड़ लगानी पड़ती है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने से पेट संबंधी बीमारी और गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीएचसी थत्यूड़ में समुचित स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण क्षेत्र के लोग उपचार के लिए 35 किलोमीटर दूर मसूरी या 70 किलोमीटर देहरादून का रुख करने को मजबूर हैं। जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अकबीर पंवार ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने से गर्भवती महिलाएं और पेट संबंधित बीमारियों की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों को जांच के लिए मसूरी और देहरादून भेजा जाता है। सीएचसी में अल्ट्रासाउंड की सुविधा होनी चाहिए। प्रधान सरस्वती रावत ने कहा कि सीएचसी में डॉक्टरों के 10 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहां मात्र चार डॉक्टर ही कार्यरत है। बाल रोग, हडडी, सर्जन और महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते लोगों को पूरा उपचार नहीं मिल पाता है जिससे लोग की परेशानी बढ़ जाती है। क्षेत्र की बह्मी देवी असवाल, ब्लॉक प्रमुख महिपाल सिंह रावत का कहना है कि सीएचसी थत्यूड़ पूर्व के वर्षों में पीपीपी मोड़ पर संचालित होता था तब अल्ट्रासाउंड की सुविधा थी।

आंधी-तूफान से घंटों गुल रही बिजली

चमोली(संवाददाता)। मंगलवार देर शाम को आंधी-तूफान से पिंडर घाटी के नारायणबगड़, थराली और देवाल में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली करीब 15 घंटे बाद बुधवार सुबह बहाल हो पाई। बिजली गुल रहने से बोर्ड परीक्षार्थियों और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीते मंगलवार रात को आंधी-तूफान और बारिश के कारण नारायणबगड़, थराली और देवाल ब्लॉक की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। हालांकि ऊर्जा निगम ने बुधवार सुबह साढ़े दस बजे करीब 15 घंटे बाद बिजली आपूर्ति तो सुचारु की लेकिन रातभर बिजली गुल रहने से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को समस्या का सामना करना पड़ा।

बक्शीर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, 92 में से 40 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

रुद्रप्रयाग(संवाददाता)। तहसील बसुकेदार के पूर्वी बांगर क्षेत्र स्थित बक्शीर में बुधवार को बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 92 शिकायतें दर्ज हुई। वहीं पिछले वर्ष आई आपदा में क्षतिग्रस्त वाहनों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत सहायता राशि के चेक भी वितरित किए गए। इस दौरान जनसुनवाई में ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों की मरम्मत, देहरादूनख्रछेनागाड़ बस सेवा पुन: शुरू करने, दूरस्थ क्षेत्रों में नए राशन वितरण केंद्र खोलने, मोबाइल नेटवर्क सुधार, विद्यालय भवन मरम्मत और रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई। वहीं जौलाखउछोला मोटर मार्ग निर्माण और छेनागाड़ख्रबधाणीताल मार्ग पर कार्य शुरू करने की भी मांग की गई। इसके अतिरिक्त ड्यूली क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए वहां स्थित बुग्यालों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का आग्रह भी ग्रामीणों द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने मौके पर ही जियो टेलीकॉम के अधिकारी से वार्ता कर शीघ्र नेटवर्क बहाली के निर्देश दिए।जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक भरत चौधरी ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान प्राथमिकता में है और लंबित कार्यों पर कार्रवाई जारी है।

आश्वासन पर नहीं माने ग्रामीण, अफसरों को गांव बुलाने की जिद पर अड़े

नई टिहरी(संवाददाता)। सड़क मरम्मत, पुल निर्माण शुरू करने, मोबाइल टावर स्थापित करने की मांग को लेकर सीमांत गेंवाली गांव के पूर्व प्रधान बचन सिंह रावत छठवें दिन भी भूख हड़ताल पर डटे रहे। उनके समर्थन में गांव की महिलाएं और अन्य लोग क्रमिक अनशन पर बैठे रहे। ग्रामीणों से वार्ता के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद के उपाध्यक्ष वीरेंद्र दत्त सेमवाल व दर्शन लाल आर्य गेंवाली गांव पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत ग्रामीणों से जिला प्रशासन से वार्ता कर जल्द समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया लेकिन ग्रामीण नहीं माने। आंदोलनरत लोगों ने कहा कि जब तब संबंधित विभागीय अधिकारी स्वयं गांव में आकर लंबित समस्याओं का समाधान नहीं करते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कहा पहले भी उन्हें अधिकारियों ने आश्वासन दिया लेकिन धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। आपदा प्रभावित 12 परिवारों का पुनर्वास, क्षतिग्रस्त जूनियर हाईस्कूल भवन का निर्माण शुरू करने सहित सात सूत्री मांग को लेकर ग्रामीण 20 फरवरी से आंदोलनरत है। धरने पर ग्राम प्रधान विजेश्वरी देवी, सुमित्रा देवी, अशरूपी देवी, प्यारी देवी, अमरदेई देवी, वीर सिंह, मखन सिंह, भीम सिंह, शिव सिंह, विक्रम सिंह, अरविंद सिंह, शेर सिंह आदि मौजूद रहे।

किशोरावस्था, कानून और रोजगार की विद्यार्थियों को दी जानकारी

नई टिहरी(संवाददाता)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर बाल सखा कार्यक्रम के तहत श्रीदेव सुमन इंटर कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में छात्र-छात्राओं को कॅरियर काउंसलिंग, बालिकाओं के लिए किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन और विधिक सेवा साक्षरता की जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सचिव / सीनियर सिविल जज आलोकराम त्रिपाठी ने छात्र-छात्राओं को बताया कि कानून के क्षेत्र में रोजगार के अपार संभावना मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को पोक्सो, चेक बाउंस, नशा, साइबर क्राइम आदि के प्रति जागरूक किया। सहायक कृषि अधिकारी अंकुर कुमार ने कृषि, उद्यान और वानिकी के क्षेत्र में कॅरियर बनाने की जानकारी दी। पूर्व प्रधानाचार्य सोमवारी लाल सकलानी ने कहा कि भविष्य में रोजगार के लिए सही लक्ष्य का निर्धारण परिस्थिति और क्षमता को समझना जरूरी है। रोजगार के लिए टीचिंग और नर्सिंग,स्वरोजगार के अलावा अनेक क्षेत्र हैं। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य रामेश्वर प्रसाद सकलानी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी मयंक थपलियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां, शैलेंद्र डोभाल, आरएस नेगी, जेएस रावत, डा. विनोद चौहान, मंजीत नकोटी, सौरभ उनियाल, दीपक रौतेला, तरुण डोभाल आदि मौजूद रहे।

डीएम ने आयुष विंग की टीम को सम्मानित किया

नई टिहरी(संवाददाता)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्कृष्ट योगदान और योग दिवस का सफल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला चिकित्सालय बौराड़ी में कार्यरत आयुष विंग को सम्मानित किया गया है। डीएम नितिका खंडेलवाल ने आयुष टीम को सम्मानित करते हुए कहा कि उन्होंने टीम भावना के साथ सराहनीय कार्य किया है। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला चिकित्सालय बौराड़ी की आयुष विंग की टीम ने सक्रिय सहभागिता के साथ कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। डीएम ने आयुष विंग के 11 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। जिनमें वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा. सत्यवीर रावत, डॉ. सिद्धि मिश्रा, चिकित्साधिकारी डॉ. कर्णपाल सिंह, डॉ. विनोद रावत, डॉ. पंकज रतूड़ी, मुख्य फार्मेसी अधिकारी बीपी बडोनी, मनोज धिरवाण, पंचकर्म सहायक रजनी सेमवाल,योग सहायक वैशाली जुयाल, रघुवीर सिंह गुसाई और सरिता खरोला आदि शामिल थे।

शिक्षा विभाग के कार्यालयों तीसरे दिन भी ठप रहा कामकाज

नई टिहरी(संवाददाता)। बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ अभद्रता और मारपीट की घटना के विरोध में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था न होने पर कर्मचारियों ने रोष जताते हुए तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया। मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और विधायक की ओर से सार्वजनिक माफी न मांगने तक कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी। मांग के समर्थन में कर्मियों ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक नई टिहरी और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरेंद्रनगर परिसर में धरना दिया। धरने पर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पूरण सिंह राणा, संयुक्त सचिव लाखीराम शाह, पूर्व जिलाध्यक्ष सोहन सिंह राणा, विरेंद्र सिंह राणा, दिनेश निराला, जसपाल केमवाल, विपुल सेमवाल, कैलशचंद्र आर्य, दिनेश रावत, जितेंद्र बिष्ट, ओमप्रकाश सेमवाल आदि बैठे रहे।

हिन्दी दैनिक जोखिम

जनभावनाओं के हिसाब से राज्य के विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है प्रदेश सरकार : सीएम धामी

देहरादून(संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मालसी, देहरादून स्थित एक होटल में हिन्दुस्तान शिखर समागम-उत्तराखण्ड 2026 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश की जनभावनाओं के हिसाब से राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले चार सालों में जनअपेक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही मदरसा बोर्ड को खत्म करने जैसे अभूतपूर्व कदम उठाकर, सनातन की इस पुण्यभूमि को हर तरह से सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ ही धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर उत्तराखंड को एक शांतिप्रिय राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 के विधनसभा चुनाव से पहले हमने राज्य में

समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी, जिस पर प्रदेश की देवतुल्य जनता का हमें पूरा समर्थन मिला। 2022 में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड देश में यू.सी.सी. लागू करने वाला पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री ने 2027 में हरिद्वार में भव्य एवं दिव्य कुंभ का आयोजन किया जायेगा। इस सबंध में वे स्वयं 10 से अधिक बैठक कर चुके हैं। केन्द्र सरकार की ओर से इसके लिए 500 करोड़ की धनराशि भी जारी की जा चुकी है, मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य कर रही है। किसी के साथ भेदभाव की भावना से कार्य नहीं किये जा रहे हैं, लेकिन छद्म तरीकों से देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने का प्रयास करने वालों पर भी सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खनन नीति बनने के बाद से उत्तराखण्ड में पिछले 02 सालों में हर साल 1200 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पहले 400 करोड़ तक रहता था। खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य को लगातार दो साल विशेष सहायता योजना के तहत 100-100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनेक महानुभावों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, हिन्दुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

एसएसपी बोले लापरवाही पर नपेंगे थानेदार और क्षेत्राधिकारी

देहरादून(संवाददाता)। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने मंगलवार देर रात जिला पुलिस की बैठक में साफ हिदायत दी कि कानून-व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें थाना प्रभारियों के साथ-साथ क्षेत्राधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। जिला पुलिस कार्यालय में हुई बैठक में एसएसपी ने ऑपरेशन क्रैकडाउन की समीक्षा करते हुए कहा कि बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित प्वाइंट के अलावा आकस्मिक स्थानों पर भी चेकिंग की जाए। पीक आवर के दौरान बाजारों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाए। इस दौरान क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को स्वयं क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना होगा।

राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में राज्य आपदा मोचक निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्तावों की समीक्षा

देहरादून (संवाददाता)। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचक निधि (ैक्त्थ्) एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (ैक्डथ्) मद के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई।बजट उपयोग में डुप्लीकेसी न हो : मुख्य सचिवमुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत विभागों को तत्काल सुरक्षात्मक कार्यों हेतु सीधे उपलब्ध कराए गए बजट तथा जनपदों में जिलाधिकारियों के माध्यम से आवंटित बजट के व्यय में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेशन न हो। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में विभागों को सीधे तथा जिलाधिकारियों के माध्यम से दिए गए बजट के सुसंगत एवं समन्वित क्रियान्वयन का विस्तृत विवरण संबंधित विभागाध्यक्ष एवं जिला अधिकारी प्रस्तुत करेंसिविल स्ट्रक्चर के साथ ग्रीनरी पर भी जोर : मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन के सुरक्षात्मक एवं मिटिगेशन कार्यों में सिविल संरचनाओं के साथ-साथ प्लांटेशन एवं ग्रीनरी सपोर्टिंग कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, जिससे समय के साथ प्राकृतिक सुरक्षा ढांचा स्वत: विकसित हो सके। सुरक्षात्मक कार्यों का टिकाऊपन सुनिश्चित करने के निर्देश: बैठक में सिंचाई विभाग, पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग सहित अन्य संबंधित कार्यदाई विभागों और एजेंसियों से सुरक्षात्मक कार्यों की टिकाऊ अवधि के बारे में जानकारी ली गई। सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए जा रहे प्रोटेक्शन कार्यों की टिकाऊ अवधि लगभग 25 वर्षों तक रहती है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी सुरक्षात्मक कार्य मिनिमम अवधि तक टिकाऊ बने रहें, इसके लिए कार्यों को गंभीरता, पारदर्शिता और टिकाऊ मानकों के अनुरूप संपादित किया जाए।अग्रिम सुरक्षात्मक प्रस्तावों का अवलोकन: मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यकारी संस्थाओं से चालू वर्ष में किए गए सुरक्षात्मक कार्यों की जानकारी प्राप्त की तथा अग्रिम सुरक्षात्मक कार्यों से संबंधित प्रस्तुत प्रस्तावों का भी अवलोकन किया।

संक्षिप्त समाचार...

राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन ने किया प्रदर्शन

देहरादून(संवाददाता)। इंडिया गठबंधन ने बुधवार सुबह बिन्दुखत्ता, बापूग्राम, पुछड़ी, बागजाला, बग्गा चौव्वन आदि के लोगों को मालिकाना हक देने की मांग को लेकर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यदि सरकार ने तीस अप्रैल तक मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन तेज होगा। पर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मांगों को लेकर एक घंटे मौन व्रत भी रखा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समाधान निकालने में असफल होती है तो एक मई को मजदूर दिवस पर सीधी कार्यवाही करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्रीमंडल द्वारा 26 दिसंबर 2016 को लिए गए निर्णय जिसे 26 दिसम्बर अधिसूचित किया गया, उसमें समाहित सभी 10 बिन्दुओं के लाभार्थियों को तत्कालिक मंत्रीमंडल की भावनाअनुरुप भूमिधरी अधिकार दिए जाने का निर्णय लिया गया था।

दून मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी में पीजी सीटों का रास्ता साफ

देहरादून(संवाददाता)। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा सेवाओं और शैक्षणिक स्तर में बड़ा सुधार होने जा रहा है। कॉलेज में डॉ. बृज नाथ त्रिपाठी ने रेडियोलॉजी विभाग में बतौर प्रोफेसर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति से अब कॉलेज में रेडियोलॉजी विषय में पीजी (स्नातकोत्तर) सीटों की मान्यता का रास्ता साफ हो गया है। प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने बताया कि प्रो. त्रिपाठी की ज्वाइनिंग से भर्ती और गंभीर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्टिंग त्वरित और सटीक हो सकेगी, जिससे इलाज में देरी नहीं होगी।

अल्मोड़ा में खड़ी होली की धूम, महिलाओं ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां

अल्मोड़ा (संवाददाता)। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली का रंग चढ़ने लगा है। मां नंदा सर्वदलीय महिला समिति की ओर से मंगलवार को नंदादेवी मंदिर परिसर में खड़ी होली का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक होली गीतों और नृत्य प्रस्तुतियों से माहौल को उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत परिक्रमा के साथ की। इसके बाद महिलाओं ने नंदादेवी मंदिर की नगर के विभिन्न मोहल्लों से आई महिला होली टीमों ने पारंपरिक होली गीतों की प्रस्तुति दी। गजानन शंभू के नंदन तेरी जय हो और होली की आई बहार फागुन महीने में जैसे गीतों के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा। महिलाओं ने सिद्धि को दाता विघ्न विनाशक, होली खेले गिरजापति नंदन, शिव के मन माही बसे काशी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जोगी आयो शहर में व्यापारी

और नैनवा रस के भरे जैसे गीतों पर भी प्रस्तुतियां दीं। इस दौरान भक्ति और श्रृंगार रस से सराबोर होली गायन के साथ रंग-गुलाल का आदान-प्रदान भी किया गया। कार्यक्रम में महिला होल्यारों ने विभिन्न स्वांग प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन भी किया। आयोजन में समिति की अध्यक्ष मीना भैसोड़ा, सचिव गीता मेहरा, उपाध्यक्ष भगवती बिष्ट, बिमला बोरा, लक्की वर्मा, गीता आर्या, किरण साह, माया वर्मा, प्रेमा बिष्ट, मोहनी कनवाल, गीता पांडे, दीपा भंडारी, हरिता नेगी, गीता बिष्ट, निर्मला जोशी, राधा राजपूत, राजेश्वरी चम्याल, ज्योति रावत और हेमा जोशी सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं।

गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ-हरिद्वार विस्तारीकरण पर प्रस्तुतीकरण

देहरादून(संवाददाता)। यूपीडाके अधिकारियों ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन के समक्ष गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण संबंधी प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में एक्सप्रेसवे के दो तुलनात्मक एलाइनमेंट विकल्प साझा किए गएख्पहला विकल्प मेरठख्मुजफ्फरनगरख्हरिद्वार जनपदों से होकर गुजरने वाला तथा दूसरा विकल्प हापुड़ख्मेरठख्मुजफ्फरनगरख् हरिद्वार जनपदों को कवर करने वाला। दोनों एलाइनमेंट पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।प्रारंभिक औपचारिकताओं व अंतरराज्यीय समन्वय पर निर्देशमुख्य सचिव ने यूपीडा को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली अग्रिम औपचारिकताओंख्भूमि उपलब्धता, यूटिलिटी शिफ्टिंग, पर्यावरणीय स्वीकृतियां, म्प् तथा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच समन्वयख्से संबंधित प्रारंभिक कार्यवाही का विस्तृत प्रारूप तैयार किया जाए। बैठक में सचिव पंकज पांडेय, अपर सचिव विनीत कुमार तथा यूपीडा से चुनकु राम पटेल, विनय प्रकाश सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन

रुद्रपुर(संवाददाता)। देहरादून में शिक्षा निदेशक के साथ अभद्रता और मारपीट के विरोध में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की ऊधमसिंह नगर शाखा ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना-प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया। बुधवार को संगठन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय परिसर में एकत्र हुए। जिलाध्यक्ष अमरदीप चौधरी ने कहा कि शिक्षा निदेशक से अभद्रता की घटना से कर्मचारियों में भारी रोष है और जिले के सभी विकासखंडों में कार्य बहिष्कार जारी है। रविंद्र पांडे ने सरकार से प्रकरण में शीघ्र निर्णय लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, ताकि कार्यालयी कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके। मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। विभिन्न विभागों के संगठन पदाधिकारियों ने घटना की निंदा करते हुए विधायक उमेश शर्मा सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कार्रवाई न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान लोनिवि मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह राठौर, फेडरेशन प्रांतीय ऑडीटर नितिन टण्डन, अनुशासन समिति अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेय, कुमाऊं मंडल सचिव हरजीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी, जनपदीय सचिव मोहित तिवारी, प्रमोद पाण्डेय, सोनिया रावत, झलक, मीना आर्या, काजल रावत, संतोष कुमारी, सरिता कुमारी, बबली, पंकज रौतेला, राजेश बलूनी, प्रदीप सिंह खड़ायत, भुवन चन्द्र ओझा, जगत सिंह, सनद शर्मा, सुरेश सिंह, नितेश शर्मा, आशुतोष सिंह, प्रकाश चन्द्र शर्मा, सुनील कुमार, उधम सिंह, भुवन भट्ट, प्रेम चंद, हरेन्द्र कपकोटी, रवि शाह, डीपी सिंह, श्वेत कुमार, कुंदन भण्डारी, मंगल सिंह आदि मौजूद रहे।

मल्ला महल में होली महोत्सव का शुभारंभ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

अल्मोड़ा(संवाददता)। मल्ला महल परिसर में महिला कल्याण संस्था अल्मोड़ा की ओर से आयोजित दो दिवसीय होली महोत्सव का बुधवार को शुभारंभ हुआ। 36वें आयोजन के पहले दिन रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। महोत्सव के तहत आयोजित होली गायन, वादन, नृत्य और स्वांग प्रतियोगिता में स्थानीय महिला समूहों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। त्रिपुरा सुंदरी महिला समिति, देवी मंदिर खत्याड़ी, कोकिला महिला सांस्कृतिक समिति मालगांव, मां जगदंबा टीम धारानौला, कुमाऊंनी सांस्कृतिक टीम स्यूनरा कोट, मां दुर्गा समिति दुगालखोला, मां दुर्गा शक्ति टीम लक्ष्मी इंद्रा कॉलोनी, महिला शक्ति ग्रुप हीर स्टेडियम, आंचल देवी न्यू कॉलोनी, नीलकंठ सत्संग समिति, दीपालय समूह और दुगालखोला की टीमों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। प्रतिभागियों ने होली गीतों, नृत्य और वादन के साथ हास्य-व्यंग्य और शिक्षाप्रद स्वांग प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा।

फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं को फंसाने की कोशिश, मुकदमा

रुद्रपुर(संवाददाता)। सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से अकाउंट बनाकर महिलाओं को फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, आवास विकास रवींद्रनगर निवासी जोगेंद्र सिंह ने तहरीर देकर बताया कि वह एक सामाजिक संगठन से जुड़े हैं। आरोप है कि आवास विकास स्थित एक निजी कार्यालय में कार्यरत शाहनवाज नामक युवक ने फेसबुक पर फर्जी नाम से आईडी बनाई है। बताया गया है कि उक्त आईडी की प्रोफाइल फोटो में धार्मिक तस्वीर लगाकर वह समुदाय विशेष से जुड़ी महिलाओं को फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से संदेश भेजकर संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। आरोप है कि वह झूठी पहचान का उपयोग कर महिलाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। ट्रांजिट कैंप थान प्रभारी मोहन पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधियों की जांच की जा रही है।

ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर(संवाददाता)। सड़क हादसे में पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, पूरनपुर पीलीभीत निवासी राकेश गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि 22 फरवरी को उसका भाई राहुल गुप्ता, पत्नी राखी गुप्ता और पुत्री आयशा गुप्ता बाइक से पूरनपुर से हल्द्वानी जा रहे थे। तभी सितारगंज में एक ट्रक ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे वे अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए। हादसें में भाई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जबकि पुत्री आयशा चोटिल हुई। दोनों गंभीर घायलों का हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

ओवरलोडिंग पर सख्ती तेज, चेकिंग में 26 वाहन सीज

रुद्रपुर(संवाददाता)। ऊधमसिंह नगर पुलिस का जिले में ओवरलोडिंग के खिलाफ सघन अभियान जारी है। मंगलवार को सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की गई। इस दौरान 26 वाहन सीज किए गए। थानावार कार्रवाई में कोतवाली कुंडा सबसे आगे रही, जहां 33 चालान किए गए। कोतवाली जसपुर में तीन चालान, एक वाहन सीज, काशीपुर में एक वाहन सीज, बाजपुर में तीन वाहन सीज और केलाखेड़ा में दो वाहन सीज किए गए। पंतनगर में पांच वाहन सीज, किच्छा में नौ चालान, तीन सीज और पुलभट्टा में ओवरलोडिंग में दो और ओवरस्पीड में एक वाहन सीज किया गया। सितारगंज और खटीमा में भी दो-दो और तीन वाहन सीज किए गए। एक दिवसीय कार्रवाई में कुल 74 ओवरलोड चालान, 22 वाहन सीज और 44 मामलों में कोर्ट चालान किए गए। इसके अलावा ओवरस्पीड के छह चालान, दो वाहन सीज और ओवरहाइट में दो वाहन सीज किए गए। एसएसपी के अनुसार अब तक अभियान के तहत 155 ओवरलोड वाहनों के चालान, 82 वाहन सीज और 83 मामलों में कोर्ट चालान किए जा चुके हैं।

नगर निगम क्षेत्र में चार आरोग्य केंद्र हुए शुरू

हल्द्वानी(संवाददाता)। हल्द्वानी नगर निगम के चार और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क इलाज शुरू हो गया है। बुधवार को मेयर गजराज बिष्ट ने केंद्रों का उद्घाटन किया। बुधवार को नगर निगम क्षेत्र के भगवानपुर, दमुवाढूंगा, नारायण नगर बिठौरिया और गोकुल नगरी कुसुमखेड़ा में मेयर गजराज बिष्ट ने अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (आरोग्य मंदिर) का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेयर ने बताया कि प्रशिक्षित एमबीबीएस डॉक्टरों की टीम सामान्य रोगों की जांच, परामर्श एवं उपचार की सुविधएं निशुल्क उपलब्ध कराएगी। बताया कि गौजाजाली और देवलचौड़ में पहले से केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

द्वाराहाट में मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण, अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश

अल्मोड़ा(संवाददाता)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की पहल पर बुधवार को द्वाराहाट क्षेत्र में विभिन्न मेडिकल स्टोरों का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में श्सुरक्षित दवाख्रसुरक्षित जीवनश अभियान के तहत की गई। निरीक्षण टीम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शचि शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर पूजा जोशी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश पाण्डे शामिल रहे। टीम ने मेडिकल स्टोरों में दवाइयों की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट और लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान कई स्टोरों में अनियमितताएं पाई गई। सात मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी करते हुए सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। एक मेडिकल स्टोर में रेफ्रिजरेटर बंद मिलने और अन्य खामियों के चलते उसके लाइसेंस को निलंबित करने की संस्तुति की गई है। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि कुछ दुकानों में एक्सपायरी दवाइयों के लिए निर्धारित बॉक्स सही तरीके से नहीं बनाए गए थे, कैश मेमो का संधारण नहीं किया जा रहा था और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं कराई गई। दवाइयों के रखरखाव और साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसे जनस्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण बताया गया। टीम ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि वे सभी ग्राहकों को अनिवार्य रूप से बिल उपलब्ध कराएं, एक्सपायरी दवाइयों का नियमानुसार पृथक भंडारण सुनिश्चित करें, कैश मेमो का नियमित संधारण करें और स्वच्छता व दवा भंडारण के मानकों का पालन करें।

मझेड़ा में नशा और अश्लीलता मुक्त होगी होली

पिथौरागढ़(आरएनएस)। होली पर्व के दौरान अक्सर लड़ाई-झगड़े देखने को मिलते हैं। पर्व के दौरान ऐसा कुछ न हो, इसके लिए सीमांत में कुछ होली कमेटियां अपने-अपने स्तर से पहल कर रही हैं। मझेड़ा होली कमेटी ने शांतिपूर्वक पर्व मनाने के लिए अराजकता करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जिला मुख्यालय से लगे मझेड़ा में होली कमेटी ने बीते रोज बैठक हुई। इस दौरान होली पर्व की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी होली पर्व उत्साह से मनाया जाएगा।

पीएम श्री एयूजीआईसी अल्मोड़ा में पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित

अल्मोड़ा(संवाददाता)। पीएम श्री एयूजीआईसी अल्मोड़ा में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन उत्साह और गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के कई पूर्व छात्र, शिक्षाविद और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई, जिसने उपस्थित लोगों को आकर्षित किया। इसके बाद प्रधानाचार्य राजेश बिष्ट ने सभी अतिथियों और पूर्व छात्रों का स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, अनुशासन, नवाचारों और विकास कार्यों की जानकारी दी। विद्यालय के पूर्व छात्र और शिक्षाविद सुशील जोशी ने संस्थान के इतिहास पर प्रकाश डाला। वहीं, पूर्व छात्र और अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए विद्यालय की वर्तमान प्रगति पर संतोष जताया और प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशी ने पुराने समय के शिक्षकों को याद किया, जबकि पूर्व अपर निदेशक अम्बा दत्त बलौदी ने शिक्षकों की भूमिका और उनके महत्व को रेखांकित किया। सम्मेलन में अंजलि अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश पांडे, पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर जी.सी. दुर्गापाल, राजकीय इंटर कॉलेज स्यालीधार के प्रध

विमल तौलिया जिलाध्यक्ष, गोपाल भट्ट बने महामंत्री

हल्द्वानी(संवाददता)। टेंट व्यापार एसोसिएशन सम्मेलन में विमल तौलिया को जिलाध्यक्ष, गोपाल भट्ट को जिला महामंत्री और केडी जोशी को जिला कोषाध्यक्ष चुना गया। प्रदेश अध्यक्ष दाऊ दयाल अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री सुभाष गुप्ता ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रमाणपत्र सौंपे। बुधवार को मुखानी रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित सम्मेलन में चुनाव अधिकारी हरजीत सिंह सच्चर, भोला दत्त भगत, कन्हैया लाल साह और जनक राज उत्पल के संचालन में चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। तीनों पदों पर एक-एक ही दावेदार सामने आने पर तीनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने टेंट व्यवसाय पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का बिगुल भी फूंका। प्रदेश अध्यक्ष दाऊ दयाल अग्रवाल ने कहा कि टेंट व्यवसाय पर 18 प्रतिशत जीएसटी पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। इसके विरोध में पूरे देश में रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने घोषणा की कि 14 मार्च को हरिद्वार में महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा। कार्यक्रम में हल्द्वानी महानगर अध्यक्ष हर्षवर्धन पांडे, महामंत्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष मनोज कपिल, कोषाध्यक्ष चंदन साह समेत नैनीताल, भीमताल, कोटाबाग, भवाली, मोटाहल्दू, कालाढूंगी, बेतालघाट, खैरना और गरमपानी के सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे।

चम्पावत में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया

चम्पावत(संवाददाता)। चम्पावत में कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने शिक्षा निदेशक से मारपीट को लेकर विरोध जताया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। चम्पावत शिक्षा भवन परिसर में बुधवार को तीसरे दिन भी कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। शीघ्र मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। विरोध जताने वालों में शुभम जोशी, मालविका पंत, गोपाल सिंह,विपिन राय, नवीन कुमार, कैलाश नाथ महंत आदि शामिल रहे।

ईशा मालवीय की डेब्यू फिल्म इश्कां दे लेखे का ट्रेलर रिलीज, 6 मार्च को रिलीज होगी मूवी

भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, डांसर, लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस 17 फेम ईशा मालवीय की पहली फिल्म इश्कां दे लेखे का ऑफिशियल ट्रेलर सोमवार को रिलीज कर दिया गया। अभिनेत्री रोमांटिक पंजाबी फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। इश्कां दे लेखे का ट्रेलर स्पीड रिकॉर्ड्स, पैनोरमा स्टूडियोज और डायमंडस्टार वर्ल्डवाइड यूट्यूब चौनलों ने आपस में कोलैबोरेशन के तहत अपलोड किया है, जिनके चौनलों पर कुल मिलाकर लगभग 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। चौनल ने मूवी का ट्रेलर रिलीज करते हुए डिस्क्रिप्शन में लिखा, एक बार फिर प्यार में पड़ने के लिए तैयार हो जाइए! स्पीड रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करता है 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित पंजाबी प्रेम कहानी इश्कां दे लेखे का ट्रेलर। शानदार गुरनाम भुल्लर और खूबसूरत ईशा मालवीय अभिनीत यह पंजाबी फिल्म उन सभी लोगों के लिए बनाई गई है, जिन्होंने कभी दिल से प्यार किया है। प्रतिभाशाली मनवीर बरार द्वारा निर्देशित, इश्कां दे लेखे बड़े पर्दे पर पंजाबी रोमांस को एक नई परिभाषा देने के लिए तैयार है। लेख और सुर्खी भिंडी जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद गुरनाम भुल्लर एक और उत्कृष्ट कृति के साथ वापसी कर रहे हैं और यह फिल्म किसी जादू से कम नहीं है। यह नई पंजाबी फिल्म प्यार की कहानी है और पंजाबी सिनेमा की सदाबहार क्लासिक बनने के लिए तैयार है। ट्रेलर की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी की बेल से होती है, जिसके बाद गुरनाम भुल्लर का सीन दिखाया जाता है और एक दमदार पंजाबी रोमांटिक डायलॉग सुनने को मिलता है, जिसमें कहा जाता है, जदो प्यार हद से गुजर जाए, उने मोहब्बत कहते हैं।

बॉक्स ऑफिस पर 11वें दिन ओ रोमियो की घटी कमाई, शॉकिंग हैं 11वें दिन का कलेक्शन

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर रोमांटिक-एक्शन थ्रिलर 'ओ रोमियो' को थिएटर में रिलीज होने के बाद से दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है, यह ट्रेंड इसके ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर फॉर्मेंस में साफ तौर पर दिखा है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे मंडे को कितनी कमाई की है. सिनेमाघरों रिलीज होने के बाद विशाल भारद्वाज निर्देशित, ओ रोमियो ने अपनी लीड जोड़ी और दमदार कहानी की वजह से लोगों को अपनी ओर खींचा. हालांकि, वर्ड ऑफ माउथ बंटा हुआ रहा, जिससे कई सर्किट में इसे थिएटर में ठंडा रिस्पॉन्स मिला. फिर वीकेंड में ये लोगों को सिनेमाघरों में खींचने में कामयाब रही. हालांकि फिर वीकडेज में इसके कलेक्शन में उतार-चढ़ाव दिखा जिसके चलते ये बंपर कमाई नहीं कर पाई. लेकिन दूसरे वीकेंड पर इसकने कमाई में थोड़ी तेजी जरूर दिखाई. अब दूसरे मंडे फिर इसके कलेक्शन में मंदी देखी जा रही है. इस बीच फिल्म की कमाई की बात करें तो 'ओ रोमियो' ने रिलीज के पहले हफ्ते में 47.1 करोड़ कमाए थे. इसके बाद इस फिल्म ने 8वें दिन 2.15 करोड़, 9वें दिन 3.4 करोड़ और 10वें दिन 3.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'ओ रोमियो ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.65 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ 'ओ रोमियो' की 11 दिनों की कुल कमाई अब 57.45 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर 'दो दीवाने सहर' में रवि उदयवार द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा है. संजय लीला भंसाली द्वारा प्रोड्यूस, ये फिल्म प्यार, पहचान और इमोशनल ग्रोथ की थीम पर बेस्ड है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, इसने पहले दिन लगभग 1.25 करोड़ से थिएटर में अपनी शुरुआत की थी. फिर वीकेंड में इसने थोड़ी तेजी दिखाई. जहां शनिवार को फिल्म ने 20 फीसदी के उछाल के साथ 1.5 करोड़ कमाए तो रविवार को इसने 3.33 फीसदी की मंदी के साथ 1.45 करोड़ का कलेक्शन किया वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दो दीवाने सहर में ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 0.65 करोड़ कमाए हैं. इसके बाद इस फिल्म की 4 दिनों की टोटल कमाई अब 4.85 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू अस्सी के लिए फिर से साथ आए हैं. ये फिल्म एक और सामाजिक मुद्दे पर आधारित है और ये कोर्टरूम कहानी है. हालांकि, भरोसेमंद जोड़ी के बावजूद, फिल्म को टिकट काउंटर पर ज्यादा कमाई करने में मुश्किल हो रही है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, अस्सी ने पहले दिन 1 करोड़ से ओपनिंग की की. इसके बाद वीकेंड में फिल्म ने थोड़ा सुधार दिखाया और इसने शनिवार को 1.6 करोड़ और रविवार को भी 1.6 करोड़ कमाए, इसके साथ, 3 दिन के ओपनिंग वीकेंड का टोटल 4.2 करोड़ हो गया. अब अपने पहले वीकडे टेस्ट का सामना करते हुए इसके कलेक्शन के नंबर फिर से कम हो गए हैं.सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को यानी रिलीज के चौथे दिन 0.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इस फिल्म की 4 दिनों की कुल कमाई अब 4.95 करोड़ रुपये हो गई है.

रियलिटी शो द 50 से बाहर आने के बाद मोनालिसा का दिखा ग्लैमरस अंदाज, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

भोजपुरी सिनेमा और हिंदी टीवी सीरियल्स की मशहूर अभिनेत्री मोनालिसा आज के समय में एक जाना-माना चेहरा हैं, जो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के अलावा शानदार डांस मूव्स के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस ने 125 से अधिक भोजपुरी फिल्मों के साथ-साथ हिंदी, बंगाली, ओडिया, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु मूवी में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। मोनालिसा हाल ही में देश के एक नए और यूनिक रियलिटी शो द 50 से बाहर आई हैं, जिसमें उन्होंने पहली बार अपने पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया था। द 50 शो के पैलेस से बाहर आने के बाद मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है। अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से कुछ बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, डोपामाइन... बेहद जरूरी। मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है, जिनका जन्म 21 नवंबर 1982 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। अभिनेत्री ने 17 जनवरी, 2017 को देश के सबसे बड़े टीवी रियलिटी शो बिग बॉस हाउस में विक्रांत सिंह राजपूत के साथ शादी की, जो कि खुद एक प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म अभिनेता हैं। मोनालिसा ने बिग बॉस 10 और टीवी सीरियल नजर में मोहना राठौड़ के रूप में बड़ी पहचान बनाई। नजर में उनके डायन के किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था। इसी के साथ भोजपुरी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री में एक मशहूर हस्ती बना दिया। अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी बोल्ड व स्टाइलिश तस्वीरों के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री की बड़ी अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिनका नाम सबसे अधिक फीस लेने वाली एक्ट्रेस में शामिल है। वहीं, मोनालिसा की भोजपुरी जर्नी की बात करें, तो उन्होंने इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, जिनमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और निरहुआ जैसे सितारों के नाम शुमार हैं।हरिशंकर व्यास भारत में तीन दशक पहले डिजिटल क्रांति आई तो भारत कंप्यूटर और इंटरनेट का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। वैसे ही डेढ़ दशक पहले सोशल मीडिया की क्रांति हुई तो भारत उसका भी सबसे बड़ा बाजार बना। भारत में अभी फेसबुक, यूट्यूब, गूगल आदि के सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। इसी तरह दो साल पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्रांति हुई उसका भी सबसे बड़ा बाजार भारत बन गया है। भारत में ओपन एआई का इस्तेमाल करने वाले सबसे

ज्यादा लोग हैं। जिस तरह से भारत आईटी क्रांति और सोशल मीडिया क्रांति का बाजार बना है उसी तरह एआई क्रांति का भी बाजार बना है।

हिन्दी दैनिक जोखिम

टिहरी में पर्यटन को नई ऊंचाई देगा लेक फेस्टिवल

– 6 से 9 मार्च के बीच आयोजित होगा टिहरी लेक फेस्टिवल

देहरादून(संवाददता)। पुराने टिहरी शहर को अपने आगोश में समाई झील की सैर, गंगा की वेगवान लहरों पर राफ्टिंग, रहस्यमयी खैट पर्वत की यात्रा से लेकर, देवप्रयाग में पौराणिक रघुनाथ मंदिर के दर्शन और संगम तट पर योगाभ्यास। यदि आप किसी एक आयोजन में इन सब गतिविधियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो 6 से 9 मार्च के बीच टिहरी लेक फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना ना भूलें। टिहरी जिला प्रशासन और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किए जा रहे भ्पउ. संलंद 2 – टिहरी लेक फेस्टिवल का शुभारंभ 6 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों किया जाना प्रस्तावित है। चार दिन के इस आयोजन के दौरान टिहरी जिले के प्रमुख केंद्रों पर विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल के मुताबिक टिहरी लेक फेस्टिवल का उद्देश्य टिहरी जिले को प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हुए, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना है। उन्होने बताया कि इस दौरान ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के साथ ही स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, मास्टर शेफ प्रतियोगिता, लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फैशन शो, फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।एक लाख रुपए तक पुरस्कार जीतने का मौका : आयोजन के दौरान अलग- अलग स्थानों पर मास्टर शेफ, फोटोग्राफी, पेटिंग, सोशल मीडिया रील, ग्रुप फैशन शो, मिस्टर एंड मिस टिहरी, राफ्टिंग, रैप सिंगिग प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। जिसमें प्रथम विजेता एक लाख रुपए तक का पुरस्कार जीत सकता है, इसी तरह दूसरे स्थान का विजेता 50 हजार, तीसरे स्थान का विजेता 25 हजार रुपए का पुरस्कार जीत सकता है, इसके साथ ही पांच- पांच हजार के 10 सांत्वना सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।पांडवाज, अमित त्रिवेदी जमाएंगे रंग : प्रतियोगिता का उद्घाटन छह मार्च को कोटी कॉलोनी में होगा। कोटी कॉलोनी में ही फूड फेस्टिवल, मिस्टर एंड मिस टिहरी, मास्टर शेफ, वीर भड़ माधो सिंह भंडारी की जीवनगाथा पर आधारित नाट्य प्रस्तुति भी होगी। कोटी कॉलोनी में छह मार्च को पांडवाज बैंड और सात मार्च गो अमित त्रिवेदी की भी प्रस्तुति होंगी। एडवेंचर टूरिज्म का पावर पैक : टिहरी जिले के दूरस्थ ब्लॉक प्रतापनगर में भी आयोजन के दौरान कई कार्यक्रम होंगे, इसमें सात मार्च को माजफ ख्र पीडी ट्रैक और आठ मार्च को थात- खैट पर्वत ट्रैक शामिल है। इसी तरह घनसाली में बासल ताल ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नरेंद्र नगर ब्लॉक में आठ मार्च को ब्रहमपुरी से खारास्रोत तक गंगा में राफ्टिंग, धनोल्टी क्षेत्र के अंतर्गत सुआखोली से देवलसारी तक एमटीबी राइड शामिल है।देवप्रयाग- आध्यात्म और योग का मेलः टिहरी लेक फेस्टिवल के प्रतिभागियों को देवप्रयाग स्थित प्रसिदध्य रघुनाथ मंदिर के दर्शन, संगम पर गंगा आरती के साथ ही योगाभ्यास का भी अवसर मिलेगा। देवप्रयाग में ही प्रतिभागियों को एतिहासिक वेदशाला का भी दौरा कराया जाएगा।।

तीन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के स्थापना दिवस पर वरिष्ठ पूर्व सैनिक सम्मानित

देहरादून(संवाददाता)। 3 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट (1/8 गोरखा राइफल्स) के स्थापना दिवस पर 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ पूर्व सैनिक और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिक संगठन ने 202वां स्थापना दिवस बड़ोवाला स्थित माधवम पार्टी हाउस में हर्षोल्लास के साथ मनाया। समारोह में रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास और वीर सपूतों को याद किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सैनिक संगठन के वरिष्ठ सलाहकार कर्नल पीबी थापा, अध्यक्ष राजेश गुरुंग और सचिव देवेंद्र गुरुंग ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अध्यक्ष राजेश गुरुंग ने रेजिमेंट के समृद्ध इतिहास को दोहराया। उन्होंने बताया कि इस बटालियन की स्थापना 19 फरवरी 1824 को कैप्टन पैट्रिक डजन के नेतृत्व में सिलहट (वर्तमान बांग्लादेश) में 16 सिलहट लोकल बटालियन के रूप में हुई थी। वर्ष 1907 में इसका नाम बदलकर प्रथम बटालियन 8वीं गोरखा राइफल्स (1/8 जीआर) रखा गया।

संक्षिप्त समाचार...

दो माह से वेतन न मिलने व सुपरवाइजरों को निकालने के विरोध में लंढौर एमडीडीए पार्किंग में प्रदर्शन

देहरादून(संवाददाता)। नगर में कूड़ा उठाने वाली संस्था के साथ कार्य कर रहे पर्यावरण मित्रों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दो माह से वेतन न मिलने व सुपरवाइजरों को निकालने के विरोध में लंढौर एमडीडीए पार्किंग में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संस्था को हटाने की मांग की। पालिकाध्यक्ष ने पर्यावरण मित्रों के साथ वार्ता की है। मसूरी नगर पालिका ने दो माह पूर्व संस्था लार्ड शिवा को घर-घर से कूड़ा उठाने का कार्य सौंपा, लेकिन दो माह बाद ही कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को 15 हजार वेतन देने पर पालिकाध्यक्ष के नेतृत्व में समझौता किया गया था लेकिन दो माह से वेतन नहीं मिला। 33 में से 25 सुपरवाइजरों को हटाया जा रहा है ऐसे में कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है कि अब वह विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे थे। अब उनका परिवार का पोषण कैसे होगा। कर्मचारियों ने कहा कि वह संस्था के अधीन कार्य नहीं करेंगे और संस्था को हटाया जाए। कर्मचारियों की मांग है कि सभी हटाये जा रहे सुपरवाइजरों का वापस लिया जाए व वेतन दिया जाए। कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने पर्यावरण मित्रों के साथ पालिका सभागार में बैठक की व उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण किया। कर्मचारियों व पालिका परिषद के बीच हुई वार्ता में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी। इसमें डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, वाहन चालक एवं हेल्पर्स से जुड़े समस्त बिंदुओं पर शिकायतों का मौके पर ही तत्काल निराकरण कर दिया गया। सुपरवाइजरों को हटाये जाने के मुद्दे पर पालिकाध्यक्ष ने कार्यदायी संस्था लार्ड शिवा के साथ एक दिन बाद विशेष बैठक करेगी व उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने पर्यावरण मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर की स्वच्छता व्यवस्था में उनका योगदान सर्वोपरि है। इस मौके पर वार्ता में पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी सहित सभासद अमित भटट, जसबीर कौर, शिवानी भारती, सचिन गुहेर गीता कुमाई, गौरी थपलियाल, विशाल खरोला, पवन थलवाल, बबीता मल्ल, रूचिता गुप्ता व पर्यावरण मित्र मौजूद रहे।

दहेज और एयरहोस्टेस से संबंधों टूटी डॉक्टर दंपति की शादी

देहरादून(संवाददाता)। मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी डॉट कॉम के जरिए मिले एक डॉक्टर दंपति की शादी चंद महीनों में ही दहेज के लालच और पति के अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गई। देहरादून निवासी महिला दंत चिकित्सक डॉ. निधि सती ने अपने पति डॉ. सक्षम अरोड़ा निवासी सहारनपुर और ससुराल पक्ष के खिलाफ रायपुर थाने में मंगलवार को उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया है। निधि की तहरीर के अनुसार पांच मार्च 2025 को दोनों का विवाह हुआ था। आरोप है कि शादी के तुरंत बाद ससुराल वालों ने हैसियत से अधिक खर्च और सोने के जेवरों का दबाव बनाया। ससुर ने घर में कमरे बनवाने के लिए मायके से पैसे लाने को कहा। मना करने पर डॉ. निधि को लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। विवाद तब और गहरा गया जब पीड़िता को पता चला कि उसके पति के एक एयरहोस्टेस (जो उसकी पेशेंट भी है) के साथ अवैध संबंध हैं।

सहकारी मेलों में वितरित किया गया 21 करोड़ का ऋण : डॉ० धन सिंह रावत

– 1000 से अधिक किसानों व स्वयं सहायता समूहों ने उठाया योजना का लाभ

– कहा, 500 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों ने मेलों में बेचे अपने उत्पाद

देहरादून(संवाददाता)। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में आयोजित सहकारिता मेलों में राज्य सरकार द्वारा किसानों, काश्तकारों, युवा उद्यमियों व महिला स्वयं सहायता समूहों को पशुपालन, मछली पालन, फूलों की खेती जैसी अन्य गतिविधियों के लिए 21 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त मेलों में 500 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों का विक्रय कर अच्छा मुनाफा कमाया है। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ० धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में सहकारिता मेलों का आयोजन किया जा रहा है। डॉ० रावत ने बताया कि सहकारिता विभाग के माध्यम से विशेष थीमों पर आधारित इन मेलों का 11 जनपदों में सफल आयोजन किया जा चुका है, जबकि टिहरी जनपद में मेला आयोजित किया गया है। इन मेलों में किसानों, काश्तकारों, कारीगरों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा मेलों में विभागीय योजनाओं का लाभ आम लोगों का पहुंचाया जा रहा है। डॉ० रावत ने बताया कि मेलों के माध्यम से अब तक 1038 किसानों व 147 महिला स्वयं सहायता समूहों को रुपये 21 करोड़ से अधिक ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा चुका है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद में 174 लाख का ब्याज मुक्त ऋण किसानों व महिला स्वयं सहायता समूहों को वितरित किया गया। इसी प्रकार बागेश्वर में 115 लाख, पिथौरागढ़ में 211 लाख, चम्पावत 81, नैनीताल 107 लाख, चमोली 155 लाख, रूद्रप्रयाग 177 लाख, पौड़ी 583 लाख, हरिद्वार 71 लाख, देहरादून 98 लाख तथा उत्तरकाशी जनपद में किसानों व महिला स्वयं सहायता समूहों को 56 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया है। टिहरी जनपद में आयोजित मेले में अब तक 270 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है। विभाग द्वारा वितरित किये जा रहे ब्याज मुक्त ऋण प्रदेश के किसानों, काश्तकारों, कारीगरों, युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों के कृषि विकास, स्वरोजगार, लघु उद्यम एवं आजीविका संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डॉ० रावत ने बताया कि सहकारी मेलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को सीधा बाजार मिला है। अब तक आयोजित मेलों में 500 से अधिक महिला समूहों ने अपने उत्पादों हस्तशिल्प, स्थानीय खाद्य सामग्री, जैविक उत्पाद सहित पारंपरिक वस्त्रों का विक्रय किया है जिससे उनको खास मुनाफा हुआ है। डॉ० रावत ने बताया कि सहकारिता मेलों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं आत्मनिर्भरता बन रही हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता मेले किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण उद्यमियों के आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। इन आयोजनों ने सहकारिता के मूल सिद्धांतों सहभागिता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से सहकारिता को रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन एवं समावेशी विकास का मजबूत आधार बनाया जाएगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक संजीव पंत द्वारा जेल रोड, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं चिराग पब्लिकेशन जेल रोड, हल्द्वानी नैनीताल से मुद्रित। **सम्पादक – राजेश पंत**
फोन नं0– 05946-254443 प्रसार प्रबंधकः वसीम अहमद , आर एन आई नं.: UTTHIN/2010/36647 email: jokhimhaldwani2013@gmail.com
ताज़ातरीन खबरों व सही जानकारी के साथ समाचार को विस्तार से पढ़ने के लिए लागआन करें हमारा newsportal:. jokhimnews.com